



C/25/7/80

भारत का अज्ञापन The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

स. ११०] मई दिल्ली, बड़वार, १४, मई १९८६/वैशाख २४, १९०८

No. 110] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 1986/VAISAKHA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली ही जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

सार्वजनिक भवनालय

आयात व्यापार नियंत्रण

मई दिल्ली, १४ मई, १९८६

सार्वजनिक भवना सं. ९६ आई टी सी (पी.एन) /८५-८८

विषय : १९८५-८६ के लिए १.५८४ विलियन येन की जापानी
भूगतान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक थोक के आयातों
के संबंध में लाइसेंसिंग घर्त।

फा. सं. ११० आई टी सी/२३(२८)/८५-८८—१९८५-८६ के लिए
सार्वजनिक थोक के आयातों के संबंध में १.५८४ विलियन येन (कठन
रहत) की जापानी भनुदान सहायता के अंतर्गत आयातों पर आसित
होने वाली गते जैसी कि इस सार्वजनिक भवना में वी. गई है जानकारी के
लिए अधिसूचित की जा रही है।

राजीव लोखन मिश्न,

मुख्य नियंत्रक, आयात एवं नियंत्र

सार्वजनिक भवनालय की सार्वजनिक भवना सं. ९६ आई टी सी (पी.एन) /
८५-८८ वित्तीक १४-५-८६ का परिचय।

आयात को सरकार द्वारा प्रशंसन किए गए १९८५-८६ के लिए येन
१.५८४ विलियन येन १,५८४,५१६,००० (कठन सहायता) की
जापानी भनुदान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक थोक के आयातों
के संबंध में लाइसेंस घर्त।

खण्ड 1. सामान्य घर्त

(1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई येन १.५८४
विलियन जापानी भनुदान सहायता और इसी और विकासशील देशों के
द्वारा संगठित की गई है। तदनुसार, इस ऋण के अधीन अधिग्राहित
की जाने वाली पाया भनुदान 'प्रौढ़ 'उनसे' संवित्र प्राप्तिक सेवाएं जापान
और भनुबंध-१ को सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती
है। वे देश इस अनुदान के अंतर्गत पाया लोत देश होंगे। इस अनुदान
सहायता के अधीन जो पाया मर्दं आयात की जा सकती है उनकी सूची
भनुबंध २ में दी गई है।

(2) लाइसेंस पर एक शीर्षक "१९८५-८६ के लिए येन १.५८४
विलियन जापानी भनुदान सहायता" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के
लिए लाइसेंस संकेत "एस.जे.एन" होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक
आयात-नियंत्रित के लिए आयात लाइसेंस के अधिकारित पत्र में भी युहराए
जायेंगे।

(3) बैंक खर्च, जिनका प्रेषण सामान्य एक प्रणाली के माध्यम से
किया जा सकता है, के अनियन्त्रित विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की
प्रत्युत्तिं आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय इमिकर्ता
कों के कमीशन के प्रति कोई भी भूगतान अभिकर्ता को भारतीय रूपए में
चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भूगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और
इसमें लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जायेंगे।

(4) आयात लाइसेंस वागन-जीमा भाडा के आधार पर 12 महीनों की प्रारंभिक वैध अवधि के मात्र जारी किया जाएगा। लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंस धारी को सबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से मम्पक करना चाहिए जो इस सामग्रे में आधिक आर्य विभाग (आयात अनुभाग) से परमर्श करेगा।

(5) एकके आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में विदेशी संभरकों वी लायत और भाडा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे (आयात लाइसेंस जारी होने वी तिथि से भार महीने की अवधि के भीतर) अवर मनिव (टी सी) आर्थिक कार्य विभाग (आयात अनुभाग), नार्य ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। “एकके आदेशों” का अर्थ विदेशी संभरकों को भारत या लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्षय आदेशों से है जो भरत या लाइसेंस धार्दा में पाप्त आदेश की पूर्ण करने के बाद “विदेशी” संभरक द्वारा विधिवत समर्पित हों या भारतीय आयातक श्रीर विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हम्मालशित कर्य मनिव हों। विदेशी संभरकों को भारतीय अधिकारीओं के आदेश और या भारतीय अधिकारीओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस गति का तब तक अनुपालन किया गया तहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेकों के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आयात अनुभाग को नहीं पहुँच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित एकके आदेश चार महीनों के भीतर वैध करायेंगे में नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश कर्यों नहीं दिए जा सके इन करायेंगों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी वी आयात लाइसेंस को सबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदन पर लाइसेंस प्राधिकारीयों द्वारा पातना के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक में अधिक चार महीनों की ओर अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। नेकिन, यदि वृद्धि इन लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारीयों द्वारा विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आयात अनुभाग) नार्य ब्लाक नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रयोग सामले की पातना के आधार पर विचार करेंगे और अपना तिर्णग लाइसेंस प्राधिकारीयों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारीयों को प्रेषित करेंगे।

पोत लदान के लिए आविर्गी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-3-1987 के बाद की न हो।

खण्ड-2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें:

(1)(क) ठेके का लागत और भाडा मूल्य ये या ये एम. डॉलर या पोण्ड स्टर्लिंग में एक येन, एक मैट या एक पैरी; से कम की भित्र के बिना ही अधिक्यवत होना चाहिए। और इसमें भारतीय अधिकारी की कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होता चाहिए जो कि भारतीय रुपय में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपय या फिरी अन्य मूड़ा में ठेके का मूल्य किसी भी परिवर्तन में अधिक्यकृत नहीं होना। चाहिए। जहाज व्यापार निःशुल्क लागत बीमा-भाडा घनरुपि अनुवात अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाडे का खर्च वास्तविक आधार पर देय होता या ठेके में विदिष्ट किए गए भाडे का खर्च वास्तविक खर्चों के अनुरूप होती।

(ख) मनिव में नकद आधार पर अर्थात बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर अनुगतान की अवस्था होनी चाहिए।

(ग) यह आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश के बाल अप्रेजी में होने चाहिए।

(2) आयात लाइसेंस के विपरीत केवल एक मनिव की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक मनिव की प्रविष्टि की अनुमति दो जारी होनी है जिनके लिए विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए।

(3) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र सोत देशों का राष्ट्रिक होता या पात्र लोत देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होता।

खण्ड-3-संभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्त विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए :-

(1) 1985-86 के लिये येन 1.584 बिलियन के अनुदान सहायता से संबद्ध इस सविदा की व्यवस्था 18-2-86 को भारत और जापान की मरकार के बोर्च है समझौते के अनुसार दी गई है।

(2) विदेशी संभरकों की भुगतान उस “भुगतान के लिये प्राविकार पत्र” (ए बी) के माध्यम से किया जायेगा जो 1985-86 के लिये जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया, टोकियो के ताम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यूसी ओ बैंक विल्डिंग, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जायेगा।

(3) विदेशी संभरक ऐसी मूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये महमन होंगा जो एक आंत भारत मरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान मरकार द्वारा अपेक्षित हो।

(4) उम सामले में, जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय दूतावास, टोकियो के पारामर्श से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और उत्तर के लिये संभरित माल को सुर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास, टोकियो को मूचन देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिये कम से कम 6 मप्पाह में पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवायेगा जिससे उचित व्यवस्था की जाये और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड-4-भारत मरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन :-

(1) जैसे ही आदेशों को अनिम रूप दे दिये जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हम्मालशित ठेके की चार प्रतियां या समुद्र पास संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिये गये क्या आदेश के साथ समुद्र पास संभरक द्वारा विधिवत रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या उनको सभी प्रकार में पूर्ण फोटो प्रतियों के जाव अनुबंध-3 के प्रपत्र में “ए/पी” जारी करने के आदेश की दो प्रतियों सहित संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों अवर मनिव (टी सी), आर्थिक कार्य विभाग, नित मंत्रालय, नार्य ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया मनिव की विषय वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आणोधनों उन्नप्र सभी संविदा संशोधनों के लिये भी लागू होंगी।

(2) यदि ठेके के दस्तावेज “ए/पी” जारी करने के लिये “आवेदन-पत्र” और अन्य संभरित दस्तावेज मंही पाये जायेंगे तो विन मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक मैट को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के राजदूतावास, टोकियो और भारत में जापान के दूजदूतावास को भेजने की व्यवस्था करेगा।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिये अनुबंध-4 के रूप में विदेशी संभरकों को भुगतान करने

के लिये “भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र (ए पी)” जारी करेगा। ए पी की प्रतिया भारत के राजदूतावास, टोकियो, आयातक, भारत में आयातक के बैंक और जमा अनुभाग, प्राथिक कार्य विभाग, विन संवालय को पृष्ठांकित का जायेगा।

4(4) भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र (ए पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया टोकियो जापान को सराहा, भारत के राजदूतावास, टोकियो, आयातक के भारत में बैंक और महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना, देते हुए इस प्राप्ति की सूचना में संभरक को अवगत करायेगा।

4(5) पोतलदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज मही पार्य गये तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित अपने बैंकरों के माध्यम से संभरक को दस्तावेजों में निर्दिष्ट धनराशि को शिलीज करेगा।

4(6) संभरक के लिये ए/पी जारी करने के लिये और भुगतान की व्यवस्था करने के लिये बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्च, भारत में आयातक के सबद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किये बिना ही निर्धारित किये जायेंगे।

खंड-5 समय जमा करने का उत्तरदायित्व :

5(1) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भार्न में आयातक के सबद्ध बैंक को भेजे जायेंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीय कूट बैंक (जो अनुबंध-3 के न में उल्लिखित हैं) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम सैट के बैल इस बात का सुनियन्त्रय कर लेने के बाद ही तंत्रज्ञ आयातक को देने चाहिये कि विदेशी संभरक को चुकाई गई येन/यू एस डालर/पौण्ड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रूपया उन सामलों में जहां देने योग्य है ब्याज के खर्च सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उन धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रूपया जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिये 12% प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिये 18% प्रति वर्ष की दर से हिसाब लगा कर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 और सं. 35-आई टी सी(पी एन)/83, दिनांक 26-8-83 के अनुसार सरकारी लेखों में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रूपया जमा किया जाता है के लिये देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना मं. 74-आई टी सी (पी एन) 74, दिनांक 31-5-74 भुगतानों को येन/यू एस डालर पौड़ धनराशि के बराबर रूपये की गणना करने के लिये अपनायी जाने वाली विनियम दर मुख्य नियन्त्रक, आयात-नियात की सार्वजनिक सूचना वं. 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनियम की स्थिति मिथित दर होगी या कह दर होगी जो कि मुख्य नियन्त्रक, आयात-नियात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियन्त्रण के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित का जाये। इस संदर्भ में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जायेगा। इस बात का सुनियन्त्रय करने का उत्तरायित्व सबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है अपने बैंकरों में दस्तावेजों की डिनीवरी लेने से पहले लाइसेंसधारी यह भी अनियन्त्रित करेगा कि देय धनराशि सही रूप से सरकारी लेखे में जमा कर दी गई है, लाइसेंसधारी जो यह सुनियन्त्रय कर देता चाहिये कि आयात-नियात परिस्थितियों में मूल पोतलदान दस्तावेजों के बगेर सामा-सुकूक प्राधिकारियों से मात्र का विवरण प्राप्त

कर लेने पर भी धनराशि सरकारी लेखे में शीघ्र जमा करा दी गई है। जिस लेखा शीर्ष से उपयोग सभ्या जमा करना चाहिये वह “के डिपोजिटस पृष्ठ एडवार्निमज-१५-न्यूयॉर्क डिपोजिटस फार पर्चेजिन्ज एट्यूटा एडवार्न पर्चेज ग्रान्ट एड फोम गवर्नमेंट आर्क जापान” पार 1935-86 (पैन 1.584 विलियन ग्रान्ट एड रुपय सहायता)।

5(2) उल्लिखित धनराशि चालान के दाहिने और कोड सं. 5130000009 दण्डि हुए या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया नीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिये या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीय कूट बैंक (हुण्डी कर्ना) से प्राप्त एक हुण्डी (डिमाण्ड ड्रापट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, नीम हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राहक और प्राप्तक) की सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68, सं. 233-आई टी सी(पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आई टी सी(पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 सं. 74-आई टी सी(पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिये धन प्रेषण करना चाहिये।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी मात्र किये जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारतीय बैंक की झगड़ निर्धारित तरीके में वह अनियन्त्रित धनराशि सेवा खर्चों के नियमित भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाये। चालान के विविध कालामों को भग्न समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनियन्त्रय कर लेना चाहिये कि सार्वजनिक सूचना में 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 2-10-76 के माथ पही जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी(पी एन)/71, के पैरा 2 में निर्धारित सूचना आर सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम “धन परेपण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण व्यौरे” में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट विवर दिये गये हैं। चालान चालान में निमनियन्त्रित और निरपवाद रूप ने प्रस्तुत करने चाहिये :-॥

(क) वित्त संवालय के भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र सं. और दिनांक ।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ नियोप किये जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि ।

(घ) चुकाये गये ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिये यह गिना जायेगा ।

(इ) जमा की गई कुल धनराशि ।

(ब्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समतुल्य रूपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिये की जानी है।

उसके पश्चात् मी प.ए पृष्ठ ए द्वारा जारी किये गये भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संग्रह करते हुए खजाना चालान रूपया जमा करने का साथ देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा मी प.ए पृष्ठ ए द्वारा भेजा जाना चाहिये।

टिप्पणी :- भारत में आयातक के बैंक को यह सुनियन्त्रय करना चाहिये कि रूपये का नियोप बैंक आफ इंडिया, टोकियो से अदायगों की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर निरपवाद रूप में किया जाना चाहिये और यह कि इसके नकाल बाद मी प.ए पृष्ठ ए, वित्त संवालय (प्राथिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को नृचिन भर दिया जायेगा।

5(4) भारत में संबद्ध बैंक भाक देहिया को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियन्त्रण प्रति पर उपयोग निवेशों का व्यवनाश का पृष्ठांकन करना चाहिये और अधिकारित “एस” प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक भाक देहिया, बम्बई की ओर से जारी कराये।

खंड-6 विविध शर्तें :

6(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्टः

भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोतलशानों और उनके अधीन किये गये भुगतानों के संबंध में भी जो पोतलशान होने वाली हैं, उनके विषय में एक भासिक रिपोर्ट सी ए एच ए, आर्थिक कार्यविभाग, वित्त मंत्रालय, यू. सी. ओ. बैंक विविध, संसद मार्ग, नई विली को भेजनी चाहिये।

6(2) संभरकों को विशेष रूप से अधिसूचित करना :

लाइसेंसधारी को चाहिये कि वे आयात लाइसेंस के उत्तर विवेष नहीं से संभरकों को भ्रवत करायें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव छात रखती है।

6(3) विवादः

यह समझ लेना चाहिये कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उनके लिये भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक भाक देहिया, दोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व तंत्रज्ञ द्वारा पूरी की जाने वाली यह साफ-साक “भुगतान के नियम” के अधीन अनुबन्ध-1 में वर्णित जानी चाहिये। विवादों से निपटने की शर्तें डेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिये।

6(4) अविष्य अनुवेशः

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले पर सभी सामर्थी में संविधित आपात से 1985-86 के लिये अनुबान सहायता के अधीन सभी आमारों को पूर्ण करने के लिये भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निवेशों या अनुवेशों या आवेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघनः

उपर्युक्त खंडों में स्थिर की गयी शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-नियर्त (नियन्त्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जायेगी।

6(6) अनुबन्धों की सूचीः

- अनुबन्ध-1 पात्र ओत देशों की सूची
- अनुबन्ध-2 पात्र उपयोग वस्तुओं की सूची
- अनुबन्ध-3 भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये आवेदन करने का प्रपद
- अनुबन्ध-4 भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपद

अनुबन्ध-1

पात्र ओत देशों की सूची

- (क) योई सी ई वेष
- प्रास्ट्रेलिया
- कनाडा
- फिनलैण्ड
- जर्मनी सार्वीय गणराज्य
- भारतसंघ
- इटली
- कानाडाम्बराने
- स्कूजीलैण्ड
- पुर्सेगाल
- स्कॉटलैण्ड
- सेनेगाल
- सिंगारा लिङ्गोम
- सूडान
- ट्रेंट अफार्स और इस्लाम
- युगान्डा
- अपर बोल्टा
- आबिया

स्लीडन	तुकी	बेलजियम	डेनमार्क	कान्स	यूताम	आयरलैण्ड	जापान	यो नीदरलैण्ड	सार्व	स्पेन	स्विटजरलैण्ड	वि. यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स	(ख)	(ख-1)	1. अफ़्रीका, जरारी सहाय	मिथ	तुनीसिया	मोरको	2. अफ़्रीका, विभिन्नी सहाय	प्रांगोला	इक्स्ट्री	प. वर्डी द्वीप समूह	चाड	इथोपिया	कांगो, दमोह गणराज्य	भाना	बोत्सवाना	केमेरू	केन्याय अफ़्रीका गणराज्य	फर्मीरी द्वीप समूह	गेबिया	इन्डोनेशिया गार्निना	गिमी	भाइवरी कोस्ट	लेसोथो	मारिलेनिया	मोजाम्बिक	पुर्तगाल गिनी	रोडेशिया	सेंट हेलिना और वेप (2)	सेनेगाल	सिंगरा लिङ्गोम	भूडान	ट्रेंट अफार्स और इस्लाम	युगान्डा	अपर बोल्टा	आबिया
--------	------	---------	----------	-------	-------	----------	-------	--------------	-------	-------	--------------	---	-----	-------	-------------------------	-----	----------	-------	----------------------------	-----------	-----------	---------------------	-----	---------	---------------------	------	-----------	--------	--------------------------	--------------------	--------	----------------------	------	--------------	--------	------------	-----------	---------------	----------	------------------------	---------	----------------	-------	-------------------------	----------	------------	-------

कीनिया	सूरिनाम
मालागासी गणराज्य	बोलिजिया
मारीशस	विली
नाइजर	फाल्फ़ेनेड द्वीप समूह
रित्युनियन	गुयाना
रवान्दा	पोइ
सौ टोम प्रिस्टीपि	उरुग्वे
सिचिलीज	5. मध्य पूर्वी एशिया
सोमालिया	बहरीन
स्वाझीलैंड	जोर्डन
टोंगो	भोमन
तंजानिया गणराज्य संघ	यूनाइटेड अरब अमिरात
जापरे गणराज्य	यमन अन्धारी भीमारा (4)
(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रवेश फरवरी द्वीप समूह।	जूगराहल
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित: असेन्शन, टिस्टन आ इन एन्सेसिव्स,	लेबनान
नाइटिगेल, गफा	सिर्याई अरब गणराज्य
(3) ऐन समूह, प्रथ्या, बोनाहरे, क्वराकामो सहा, सेंट युस्टालिंट,	यमन अरब गणराज्य (3)
सेंट मार्टिन (दक्षिणी भाग)।	6. दक्षिणी एशिया
3. अमेरिका-उत्तरी और केन्द्रीय	अफगानिस्तान
बहमन	भूटान
बोलाईज	भास्त्रीप
फोर्टारिका	पाकिस्तान
बोमिनिकल गणराज्य	बांगला देश
गुआचिलागप	बर्मा
हैटी	बिपाल
जैमेका	बी लंका
बारबाडोज	7. सुहूर पूर्वी एशिया
बर्मडा	बुर्मे
क्यूबा	बेरर गणराज्य
एल सल्वाडोर	जाओरस
ग्याटेमाला	मलेशिया
होम्बरस	सिंगापुर
माटिनिकक्यू	आईलैंड
मैक्रिस्को	बियतमाम गणराज्य
निकारागुआ	बियतनाम अन्धारी गणराज्य
सेंट पियरी और मिल्युलोन	हाँगकाँग
सैन्ट इण्डिया (आ०) एन०आई०ई०	फोरिया गणराज्य
(क) संबंधित राज्य (1)	भकार्डो
(ख) प्राथित राज्य (2)	फिलीपाइन
भीवरलैंड	ताइवान
पतामा	तिमोर
ट्रिनिडाड और टायपो	गणराज्य
4. दक्षिणी अमेरीका	
पर्जन्यीया	
बाझील	
कोलम्बिया	
फासिसी गिनी	
पाराग्वे	

- (1) मृश्य दीप एस्टिग्युला, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेंट किल्स (सेंट करिस्टोफे), बेनिस बैग्ज़िना, सेंट लुसिया और सेंट विंसेंट।
- (2) मैन आई लैन्ड, ब्रोन्टेमे रोट, गेमान, त्रुकी आर काइकोह और विटिश वर्गिन्स प्रमुख।
- (3) अजमत, दुर्वर्द, कजाइरह, रास भल चॉम्पाह, मोरजाह और उम्मल बचेकन।
- (4) प्रदून और विमिन सुलतनत और अमीरात सहित।
- (5) गोसाईटी आईलैंड्स समूह (नाहिमी सहित) को शामिल करते हुए ग्रान्ड दीप भवूह, दुप्रामाट, जांकियर ग्रूप और मार्फेसल दीप समूह।
- (6) वैसिपिक दीप समूह का द्रष्ट प्रवेश, कारोलोन दीप समूह, मार्फेल दीप समूह और वेरिना दीप समूह (गाम को ओडकर)

8.

कोक दीप समूह

गिल गिलबर्ट और इलाइट दीप

नोर्थ

न्यूदीपिसेस (विं भार क०)

वैसिपिक दीप समूह (संयुक्त राज्य), (6)

फिजी

फ्रांसिसो वैलिनेशिया (5)

स्ट्रू कोलोडोनिया

हिपू

पापुआ न्यू गिनी

सोलामन दीप समूह (हि०)

वालिम और कतुगा

टोगो

परिषद समाजी

9. धूरोप

साइप्रस

स्त्रीक

स्पेन

युगोस्लाविया

जिब्राल्टर

माल्टा

त्रूपी

वाण्ड-2 ओ०पी०ह० सी० के सदस्य या सहयोगी ऐसा:

प्रलीलिया

बोलिलिया

देशान

इक्वेडोर

ईरान

कुवैत

भारूदावी

मउदी प्रदून

लीयाइद फरवर गणराज्य

नाइजीरिया

बेन्जुएला

द्वितीय
कातार
इन्डोनेशिया

प्रनवध-2

पात्र पाँच सूची

1. रोन्ड
2. विशेष इस्पात और मिश-धातु इस्पात संहेत इस्पात
3. द्वीपी और ट्रैटटोरो के वित्तिमान के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे
4. रसायन
5. जापान भवुतान परियोजना और भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे, संघटक और कलन्दू पुर्जे।
6. विजली के हुकों के लिए संघटक, संयोजक, फालतू पुर्जे और कलन्दू पुर्जे।
7. मशीनरी, संघटक, संयोजक, फालतू पुर्जे और कलन्दू पुर्जे।
8. संयुक्त उद्योग क्षेत्र के लिए मशीनरी और उपकरण
9. तेस एवं प्राकृतिक गैस घोत के लिए मशीनरी, उपकरण और फालतू पुर्जे।
10. उद्योग और ऐसी अन्य मर्जे, जिन पर धारण में सहमति हो।

प्रनवध-3

"भूगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र"

सं. :

दिनांक :

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परिया नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय
प्राधिक कार्य विभाग,
पु.सी.ओ. बैंक विलिंग्न,
प्रथम मंजिल,
पालियामेंट स्ट्रीट,
नई विल्सी-110001.

विषय :— 1985-86 के लिए येन 1,584 वित्तियत जारी करना
भवुतान सहायता येन के अंतर्गत जापान से आयात।

महोदय,

उपर उल्लिखित भवुतान सहायता के अंतर्गत जापान से जो हि...
आयात के संबंध में है संबद्ध संभरक के नाम में ऐसे नाम हैंडिया, टोकियो के लिए भवुतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आपको गिम्बलिंगित व्योरे प्रस्तुत करने हैं—

- (क) मार्केट प्रायातक का नाम और पता।
- (ख) आयात आइसेंस की सं., दिनांक और मूल्य यों बहु तरीख वित्त तक वैध है।
- (ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या शोपलाइक व्युने प्रबन्ध-राष्ट्रीय निविदा पर प्राप्तारित है। इसके साथौरे ऐसे कोई कारण ही तो कारण नाहिन यह संकेतित होता चाहिए कि वित्त संविदा का निर्णय उपयुक्त सूत्रतभ तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
- (घ) मात्र का मंजिल विवरण।
- (इ) मात्र का उद्देश्य देश
- (ज) संविदा का कुल जागत मात्रा मूल्य (येन में)
- (झ) यदि कोई हो तो भारतीय एए में भवुतान की जान भारती भारतीय एजेंट के कमीशन की जानकारी।
- (ञ) वह कुल जागत तथा भारत मूल्य (येन में) इसके लिए भवुतान के लिए प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता है।

(म) सरकार के गायत्री नाम संस्कृत को मंत्रालय और देश का
 (न) संस्कृत का नाम और पता
 (ट) वे भगवान थे जो श्री वंशवित तिर्तुल विद्वान् नामका का उत्तीर्ण
 मृगतान देख देंगे।
 (ठ) मृगदेवी को गणे करने की प्रस्तावित तिर्तुल
 (ड) भारतीय बैंक ट्रॉफियो को भूगतान करने वस्त्र किए देने वाले वर्षावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और निर्दात का इकाई कर्त्ता के मेटों की संख्या और उनका निराल विप्रो है।
 (इ) पीन-नदान प्रनुदेश (शाहनामन्त्र/पार्ट-गिरमेंट) की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट की गयी।
 (ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।
 (क) क्या इसी स्लाइरेस के अन्तर्गत संविदा (संविधानों) करणी गई है। यदि तो, तो ऐसी निर्दात का दिनांक घोर मूल्य।
 (क्ष) वह भागीदार पतन जहाँ उपर्युक्त/मामदी पोत आया था।

प्रारूप - 4

संदेश
भारत सरकार
विभ. मंत्रालय
आधिकारिक कार्य विभाग
नई विभागीय दिविनिक

सेवा नं.

बैंक आक हैंडिया,
टॉकियो शाखा,
टॉकियो (जापान)।

विषय: यैन 1. 584 विलियन के लिए जागत्र वह भूगतान मंडायन के अधीन आधार भूगतान के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्वारा यथा संलग्न व्योरे (जो परिवर्तन में बदला गया है) के अनुसार संबंधी के नाम में विवरण देने वाले वह धनराशि के भूगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. छपया भूगतान वे लिए प्राधिकार-पत्र (ग/पी) की पावसी के बारे में संभरकों का सूचना दें और हमको प्रत्येक भूगतान पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक, भारत के गण-दूतावाल, टॉकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भूगतान के लिए प्राधिकार-पत्र की शर्तों के अनुसार भूगतान गणित में यथा संकेतित लदात दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. विविधों संभरक को भूगतान करने पर आपको (आयातक के बैंक का नाम और पता) को नमी मूरा का मंत्रालय दस्तावेजों (परकाम्य) के राष्ट्र-सामय दस्तावेजों तक एक पूरा फैट और यदि कोई नकद भूगतान हो उसके सहित संभरक को किए गए भूगतानों के लिए नाम बोक की एक प्रति भेजनी चाहिए।

5. आयातक द्वारा आपको दातावेजों को भेजने जाति के लिए आपको महिला छवि या जाते थाले बैंकिंग और टॉकियो में भारतीय दूतावाल/आयातक के दैक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

6. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वामित्व के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भूगतान किया जाता है तो इनकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजो जानी चाहिए।

7. इस मंत्रालय को विशेष ग्रन्ति मिली के बिना भूगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संरक्षण जारी नहीं किया जा सकता है।

8. यह भूगतान के लिए प्रारूप-पत्र के विवरण विवरण विवरण विवरण विवरण।

9. ऐसे ग्राहक भूगतान दिवाल वाले भी जारी की गयी विवरण विवरण विवरण विवरण। इस भूगतान प्राधिकार पत्र के विवरण पर दोनों संघर्ष उद्धृत करें।

धर्मीय,
लेका प्रविकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. आयातक को उनके पत्र संख्या दिविनिक के संभरण में।

2. आयातक का बैंक के संभरण में।

(i) यह प्राधिकार पत्र यैन भूगतान के अन्तर्गत आयातों पर आसित संगत लाइसेंसिंग शर्तों के अन्तर्गत जारी किया गया है। आयात/विवेशी भूगतानों के संभरण में लाइसेंसिंग शर्तें और संबंधित सार्वजनिक सूचना सं. 8-प्राईटी सी (पी एन)/76, दिविनिक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-वस्त्र के अनुसार विवेशी संभरकों को भूगतान करने की विधि को यथा प्रत्यक्षित परिवर्तन की मिथित वर पर की जाएगी। विवेशी संभरकों को भूगतान करने की विधि से जरूरार के लिए में तुल्य रूपया जमा करने की विधि वक्त की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं. 31 प्राईटी सी (पी एन)/83, दिविनिक 10-3-83 और सं. 36-प्राईटी सी/पी एन/83, दिविनिक 26-3-83 के अनुसार पहले, 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत आधिक वर पर ग्राहक की प्रतिशत वर की गई भवधि के लिए 18 प्रतिशत की दर से आया भी 10 दिनों से अधिक वर की जमा करना होगा। आया वोनों दिनों के लिए दिया जाएगा वर्षात् वह विधि जिसका विवेशी संभरक को भूगतान किया जाता है ग्राहक वह विधि भी जिसको सरकारी लेके में राया निलेप किया जाता है। (इस वर में यदि कोई परिवर्तन किया जाता हो तो तुल्य अधिसूचित किया जाएगा)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सोमा-शुल्क निकासी के लिए आधार दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जाए है।

(ii) यैन धनराशियों जापान के दाविते ग्राहक सं. 5130000009 विवेशी द्वारा या तो ग्रिज्व बैंक आक हैंडिया, नई विलिनो या स्टेट बैंक आक हैंडिया, तीस हजारी, विलिनो में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आक हैंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुबंधी संस्थाओं या किसी भी ग्रामीणकृत बैंक से उनके हारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आक हैंडिया तीस हजारी शाखा विलिनी-6 (आधेशित और आयाता) के नाम में ग्राहक उनको देय हारी हुए हो के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका धनराशियों सूचना सं. 23-प्राईटी सी (पी एन) 68, दिविनिक 24-10-68 क. 132-प्राईटी सी (पी एन) 71, दिविनिक 5-10-1971 क. 74-प्राईटी सी (पी एन) 74, दिविनिक 31-5-74 और सं. 103-प्राईटी सी (पी एन) 76 दिविनिक 12-10-76 की शर्तों को आर विलापा जाता है। लेका शीषे जमाए धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवानस-843 तिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परवेजिन एट्सेक्टा एवार्डवरवेजिस एण्ड एडवेंट फार्म दि गवर्नर्मेंट आर जारी" का 1935-83 (यैन 1. 584 फिलिन आर एण्ड डेविट रिलिन)।

(iv) जिन मामलों में तुल्य रूपया ग्रिज्व बैंक आक हैंडिया, नई विलिनी या स्टेट बैंक आक हैंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132-प्राईटी सी (पी एन) 71, दिविनिक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता

है उनमें आवान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया टोकियो शाखा से साप्त सूचना दिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अधेशग पत्र सहित उनके हाथा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएँगी:—

सहायता देखा नया लेखा परीक्षा नियंत्रक वित रंगायर (प्रांयक कार्य विभाग) पहली मंजिल यू.सी.आ. बैंक विल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

(v) जिस मामले में तुल्य रूपया उपर संकेतित नारंजिक सूचना विभाक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्णनी हुए ही बारा प्रेषित करता है उसकी सूचना उभयक पते पर भेजी जाना चाहिए। सभी मामलों में व्याज की चुकाई गयी '1' प्रतिशत धनर और शिक्षित अवधि के लिए व्याज की गणना की गई है और उत्कृ तात्पर्य जूदा किए गए तुल्य रूपया का पूरा ध्योग इस विभाग की सेवना चाहिए।

(vi) समुद्रापार संभरक के बैंकर के खातों प्रतिवर्ष कोड़े हो तो, बैंकिंग बच्चे और बैंक आफ इंडिया टोकियो बांब के अन्य बच्चे इंडियन बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निवारित किए जाएँगे।

(vii) विदेशी मुद्रा विनियम में बैंक के प्राधिकरण डीलर के रूप में कर्तव्य और उत्तराधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न ए.डी. परिषदों में निर्वाचित किए गए हैं। इस संदर्भ में 18-6-1977 के ए.डी. परिषद स. 22 की ओर विशेष ध्यान विलापा आता है।

4. भारतीय दूतावास टोकियो।

5. धनर सचिव (टी.सी.) शाखा, वित मंत्रालय, भारतीय कार्य विभाग, नई दिल्ली को उनके पार्स द्वारा सं.....
आपान विनाक के संदर्भ में।

लेखा अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
New Delhi, the 14th May, 1986

PUBLIC NOTICE NO. 96 ITC(PN)|85—88

Subject : Licensing conditions in respect of Public Sector imports under Japanese Debt-Relief Grant Aid of Yen 1.584 billion for 1985-86.

F. No. IPC|23(28)|85—88.—The terms and conditions governing imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1.584 billion (Debt Relief) for 1985-86 in respect of Public Sector imports, as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports.

Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No. 96-ITC(PN)|85—88 dated the 14th May, 1986. Licensing Conditions in respect of Public Sector imports under Japanese grant Aid of Yen 1.584 billion (Yen 1,584,516,000) (Debt Relief) for 1985-86 extended by the Government of Japan.

Section I.—General Conditions :

I(i) The Japanese Grant Aid of Yen 1.584 billion extended by the Government of Japan is united in favour of OECD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list

at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I(ii) The licence will bear the superscription "Yen 1.584 billion Japanese Grant Aid for 1985-86". The licence code for the first and second suffix will be "S|JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract only signed by both the Indian importer and the Overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why orders could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merit by the licencing authorities who may grant further extension upto a maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such pronosals will invariably be referred by the licencing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licencing authorities for communication to the licence.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-87.

Section II—Special points to be kept in view while Negotiating a supply contract.

II(i)(a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one cent or one penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained so on after the date of issue of the import licence.

II(iii) Eligibility of Supplier

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract:—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 18-2-86 between the Government of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 1.584 billion for 1985-86 "and will be subject to the approval of Government of India".

III(ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay (A/P)' which will be issued by the Controller of Aid Account and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1985-86.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional case, where the importer require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each

shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by Govt. of India.

IV(i) As soon as the orders are finalised, the licences should forward to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the Overseas supplier supported by order confirmation in writing by the Overseas supplier of their photo copies complete in all respects with two photo copies of the relevant valid import licence and also two copies of the request for issue of A/P" in the form at Annex. III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(ii) If the contract documents "Request for issue of A/P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A, the Embassy of India, Tokyo and the Embassy of Japan in India.

IV(iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Account & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an Authorisation to Pay (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV(iv) On receipt of the Authorisation to pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

IV(v) The foreign supplier shall, after effecting shipment present through his banker, the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section V—Responsibility for rupee deposit.

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's Bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Bank as mentioned in (C) in Annexure-III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen/US\$| Pound sterling payments made to the supplier along

with interest charges thereon in cases where payable calculated at the rate of 12 per cent annum for the first thirty days and at 18 per cent for the period in excess therof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC(PN)83 dated 10-8-83 and No. 35-ITC(PN)83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)74 dated 31-5-74 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen/US\$ £ Payment will be prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited in to the Govt. account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances 843-Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad—purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1985-86 (Yen 1.584 billion Grant Aid Debt-Relief).

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 513000000 on the right hand corner of the challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public notices No. 184-ITC(PN)68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)68 dated 24-10-68 and No. 132-ITC(PN)71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)76 dated 12-10-1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of Service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that the information prescribed in

para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)71 dated 5-10-1-71 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A|P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversation adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit, should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VI—Miscellaneous provisions

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence.

**The importer should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping etc. documents by the importers Banker will not be acceptable as a reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions :

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in

Annexure—I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI(iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with directions, instructions or orders issued by the Govt. of India from time to time regarding any and all matters arising or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1985-86 from Japan.

VI(v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act). VI(vi) List of Annexures.

Annexure-I List of eligible source countries

Annexure-II List of eligible commodities

Annexure-III Form of Request for issue of Authorisation to pay (a A|p).

Annexure-IV Form of letter of Authorisation to Pay (A|p).

The importer should send a monthly report, after the A|P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

ANNEXURE—I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. OECD Countries

Australia
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
The Federal Republic of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxemburg
the Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
the united Kingdom and the United States.

B. Developing Countries & Territories

(b) Non-OPEC Developing Countries

- I. Africa, North of Sahara
 - Egypt
 - Morocco
 - Tunisia
- II. Africa, South of Sahara
 - Angola
 - Botswana
 - Burundi
 - Cameroun
 - Cape Cards Islands
 - Central African Rep
 - Chad
 - Comoro Islands
 - Congo, People's Republic of
 - Dahomay (1)
 - Equatorial Guinea
 - Ethopia
 - Gambia
 - Ghana
 - Guinea
 - Ivory Coast
 - Kenya
 - Lesotho
 - Libaria
 - Malagasy Republic
 - Malawi
 - Mali
 - Mauritania
 - Mauritius
 - Moozambique
 - Niger
 - Portuguese Guinea
 - Reunion
 - Rhodesia
 - Rwanda
 - St. Helena and Dep (2)
 - Sao Tome and Principee
 - Senegal
 - Seychelles
 - Sictra Leone
 - Somalia
 - Sudan
 - Swaziland
 - Terro, Afars and Isses
 - Tago
 - Uganda
 - Un. Rep. of Tenazania
 - Upper Volta
 - Zaire Republic
 - Zambia

- (1) Formerly the territory of Spanish Guinae, including the island of Fernando Po.
- (2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough
- (3) Main islands, Aruba, Fonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit, St. Martin (Southern Part).

III. AMERICA, North and Cent

Bahamas
 Barbados
 Belize
 Barmuda
 Costa Rica
 Cuba
 Dominican Republic
 El Salvador
 Guadeloupe
 Guatemala
 Haiti
 Honduras
 Jamaica
 Martinique
 Maxico
 Netherlands Atilles

Nicaragua
 Panama
 St. Pierre & Miquelon
 Trinidad and Tabago
 West Indies (Br.) n.i.e.
 (a) Associated States (1)
 (b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South

Argentina
 Bolivia
 Brazil
 Chile
 Colombia
 Fullkland Islands
 French Guiana
 Guyana
 Paragusy
 Peru
 Surinam
 Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
 Israel
 Jordan
 Lebanon
 Oman
 Syrian Arab Republic
 United Arab Amirates (3)

Yemen Arab Republic
 Yemen, People's D.R.(4)

VI. ASIA, South

Afghanistan
 Bangladesh
 Bhutan
 Burma
 Maldives
 Nepal
 Pakistan
 Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Burnei
 Hong Kong
 Khmer Republic
 Korea, Republic of Laos
 Macao
 Malaysia
 Philippines
 Singapore
 Taiwan
 Thailand
 Timer
 Vietnam, Rep. of
 Viet-Nam Dem. Rep.

(1) Main islands; Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(2) Main islands : Montserrat, Gayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Ummal Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (Including Tahiti), The Austral Islands, the Tuametu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

VIII. Cock Islands

Fiji
 Gilbert & Ellice Is.
 French Polynesia (5)
 Nauru
 New Caledonia
 New B Hebrides (Br. and Fr.)
 Niue
 Pacific Islands (US) (6)
 Papua New Guinea
 Solomon Islands (Br.)
 Tonga
 Wallis and Futuna
 Western Samoa

IX. EUROPE

Cyrus
 Gibraltar
 Greece
 Malta
 Spain
 Turkey
 Yugoslavia

(b2) Member or Associate Countries of OPEC

Algeria
 Bolivia
 Libyan Arab Republic
 Gabon
 Nigeria
 Ecuador
 Venezuela
 Iran
 Iraq
 Kuwait
 Qatar
 Saudi Arabia
 Abu Dhabi
 Indonesia

ANNEXURE—III
 "REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
 Ministry of Finance,
 Department of Economic Affairs,
 UCO Bank Building, 1st Floor,
 Parliament Street,
 New Delhi-110001

Subject : Import under the Japanese Debt-Relief Aid
 of Yen 1,584 billion for 1985-86.

Sir,

In connection with the import of _____ from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

- (a) Name and Address of the Indian Importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agents commission (in Yen) if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) Name and date of the contract with Suppliers.
- (j) Name and address of the Supplier.
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo, (incl. indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transhipment/part shipment permitted or not permitted).
- (o) Name and address of the Importer's Bank in India.
- (p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.
- (q) Indian port to which the equipment/materials are to be shipped.

ANNEXURE—II

ELIGIBLE COMMODITY LIST

1. Rolls
2. Steel including special steel & alloy steel
3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors
4. Chemicals
5. Spares, components and raw materials for Japan aided Projects and Indo-Japanese Joint Ventures.
6. Components, attachments and spares for power tillers
7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials.
8. Machinery and equipment for the Small Scale Sector.
9. Machinery, equipment and spares for the Oil & Natural Gas sector
10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

ANNEXURE-IV

No.
**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS**
New Delhi, the

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Sub. :—Import under Japanese Debt-Relief Grant
Aid of Yen 1.584 billion—Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated _____ entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen _____ to M/s. _____ (as per details given in the Appendix).

2. Please advise the suppliers of the fact of receipt of this authorisation to Pay (A|P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers' Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A|P will be made on the basis of shipping documents etc. as indicated in the Appendix.

4. On making payment to the foreign suppliers, you should send to _____ (Name & address of importers' Banker) all the original shipping documents (negotiable) as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any.

5. The banking charges including charges for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India, Tokyo Importer's Bank.

6. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

7. No amendments to A|P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

8. The A|P will remain valid upto _____.

9. Please quote the number given at the top of this Authorisation to Pay in all correspondence relating to the contract and also in the advices showing payment.

Your faithfully,
Accounts Officer.

Copy forwarded to :—

1. Importer _____ with reference to their letter No. _____ dated _____.

2. Importers' Banker _____.

(i) This authorisation to pay is issued under the relevant licensing conditions governing the imports under Yen grants. The licensing conditions and connected Public Notices/orders etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import/foreign payments.

(ii) _____ They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen 1|4 US\$ £ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo, Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 12 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 18 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Govt. Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-83 and No. 35-ITC(PN)|83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be notified if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

(iii) These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 513000009 on the right hand corner of the challan or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notice No. 23-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K—Deposits and Advances—843—CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid From the Government of Japan" for 1985-86 (Yen 1.580 billion Grant Aid-Debt Relief).

(iv) One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

(v) In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest 1 per cent and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

(vi) The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas

suppliers bankers, if any should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

(vii) The Banks' duties and responsibilities as authorised Dealer in Foreign Exchange as prescribed in various A.D. circulars of the Reserve Bank of India. Specific references in this regard is invited to A. D. Circular No. 22 dt. 18-6-1977.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, (TC) Ministry of Finance,, Department of Economic Affairs, New Delhi-110001 with reference to ID No. [Jap. dt.

(Accounts Officer)